

**ALL INDIA DEFENCE EMPLOYEES' FEDERATION**  
**BHARTIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH**  
(RECOGNIZED FEDERATIONS OF DEFENCE CIVILIAN EMPLOYEES)  
**CONFEDERATION OF DEFENCE RECOGNIZED ASSOCIATIONS**  
**NATIONAL PROGRESSIVE DEFENCE EMPLOYEES FEDERATION**  
**ALL INDIA BAHUJAN DEFENCE EMPLOYEES FEDERATION**

---

Joint Circular No. : 29/2021

Date : 07.09.2021

**REFERENDUM ON CORPORATISATION OF 41 ORDNANCE FACTORIES**

**LET EACH AND EVERY WORKER EXPRESS THEIR  
VERDICT ON CORPORATISATION.**

**REFERENDUM WEEK ON CORPORATISATION FROM  
13/09/2021 TO 18/09/2021**

All of you are aware that inspite of all our stiff protest and ongoing agitations and also gathering the support of all Trade Unions, social organisations, political parties, Members of the parliament and eminent people from different walks of life against the ill advised decision of the Government to Corporatise the Ordnance Factories by declaring them as 7 Companies, the Government is bent upon to go ahead with their decision.

You are also aware that apart from different form of protest organised by the Federations, we have also decided to take legal recourse on the Government's decision for corporatisation and bringing in dreaded EDSA against the employees of Ordnance Factories to silence their genuine voice of right to protest. We are in the final stages of filing petitions against EDSA and Corporatisation.

You are aware that the INDWF has already taken a position in support of the Govt. decision to Corporatise the Ordnance Factories against the interest of the employees. Taking advantage of this the DDP/MoD is moving fast to implement the Govt. decision by issuing various instructions almost on a daily basis. In this situation to ascertain the ground reality and to convey the firm views of the entire work force of Ordnance Factories, it has been decided to hold a Referendum in all the Ordnance Factories

Accordingly it has been decided to hold a Referendum from amongst the employees of Ordnance Factories irrespective of category on the decision of Ministry of Defence to splinter the Ordnance Factories in to 7 Corporations and to show them that the decision taken by the Government is ill conceived, illogical and totally against the interest of Security and Defence preparedness of our country. Accordingly it has been

decided unanimously by AIDEF, BPMS, CDRA, NPDEF & AIBDEF to conduct a Referendum on any day depending upon the local situation during the week commencing from 13/09/2021 to 18/09/2021. A model Referendum ballot paper is enclosed herewith. Two ballot boxes may be kept in the entrance of the Factory Gate, one painted with Black colour which is in favour of corporatization and another one painted with white colour which is against Corporatisation. We may approach each and every employee and educate the employee to cast their choice in the Referendum against Corporatisation and to remain as Government Employee till superannuation. After the polling is over the Votes may be counted and the results may be informed to the respective Federations immediately which we will consolidate and forward to the Government. The Unions/JAC should inform the result to the General Manager in writing. In the Ballot paper the names of AIDEF, BPMS, CDRA should be printed. In the Factories where NPDEF and AIBDEF affiliated Unions are functioning in those Factories, the name of NPDEF and AIBDEF may also be printed.

### RESULT OF THE REFERENDUM MAY BE FORWARDED TO THE FEDERATIONS IN THE FOLLOWING FORMAT

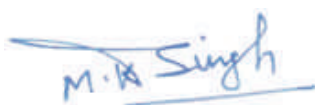
- 1) Name of the Factory \_\_\_\_\_
- 2) No. of employees of the Factory \_\_\_\_\_
- 3) No. of Employees participated in the Referendum \_\_\_\_\_
- 4) No. of Employees voted against Corporatisation \_\_\_\_\_
- 5) No. of Employees voted in support of Corporatisation \_\_\_\_\_

(To be signed by the General Secretaries of the Unions which conducted the Referendum with Federation name)



**(C. SRIKUMAR)**  
GENERAL SECRETARY  
AIDEF

09444080885 / 9421081035 (Whatsapp)    defempfed@gmail.com



**(MUKESH SINGH)**  
GENERAL SECRETARY  
BPMS

09335621629    gensecbpms@yahoo.co.in



**(VIJAY P DHYANI)**  
GENERAL SECRETARY  
CDRA

09999766016    gscdra@gmail.com



**(V. VELUSWAMY)**  
General Secretary/NPDEF  
9444471845  
velu10swamy@gmail.com



**(MUKESH KUMAR)**  
General Secretary/AIBDEF  
9540513330

Ballot Paper Sl.No. :

Date : \_\_\_\_\_

## REFERENDUM - 2021

Name of the Factory \_\_\_\_\_

**AIDEF, BPMS, CDRA, (NPDEF & AIBDEF in the  
Factories wherever affiliated Unions are there)**

### **FORM OF BALLOT PAPER**

- 1) I oppose and reject Corporatisation and wanted  
to continue as Central Government /  
Defence Civilian Employee



- 2) I support Corporatisation of  
Ordnance Factories



**ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन**  
**भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ**  
(रक्षा असैनिक कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त महासंघ)  
**कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन्स**  
**नेशनल प्रोग्रेसिव डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन**  
**ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन**

संयुक्त सर्कुलर सं. 29/2021

दिनांक 07.09.2021

**41 आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के ऊपर जनमत संग्रह !**

**निगमीकरण के ऊपर प्रत्येक कर्मचारी को अपना निर्णय व्यक्त करने दें।**

**निगमीकरण के ऊपर जनमत संग्रह सप्ताह**  
**दिनांक 13.09.2021 से 18.09.2021 तक।**

आप सभी जानते हैं कि, हमारे कड़े प्रतिरोध तथा जारी आन्दोलनों के साथ ही साथ सभी ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों, राजनैतिक पार्टियों, संसद सदस्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त हो रहे जन समर्थन के बावजूद भी सरकार के द्वारा एक बीमारू सलाह के आधार पर, आयुध निर्माणियों को 07 कम्पनियों में तब्दील करते हुये उनका निगमीकरण करने का फैसला लिया गया है तथा सरकार अपने फैसले के साथ आगे बढ़ने पर पूरी तरह से आमादा है।

आप सभी यह भी जानते हैं कि, महासंघों के द्वारा आयोजित किये गये विभिन्न स्वरूप वाले विरोध कार्यक्रमों के अलावा हमने, सरकार के निगमीकरण के फैसले तथा अन्याय के खिलाफ जायज आवाज को चुप कराने के लिये आयुध निर्माणियों कर्मचारियों के खिलाफ लाये गये खूँखार “**आवश्यक रक्षा सेवार्ये अधिनियम-२०२१**” के विरोध में, कानून का भी सहारा लेने का निर्णय लिया है। हम, आवश्यक रक्षा सेवार्ये अधिनियम एवं निगमीकरण के विरोध में याचिकायें दाखिल करने के अंतिम पायदान पर हैं।

आप सभी जानते हैं कि, आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ. के द्वारा पहले ही कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध, आयुध निर्माणियों का निगमीकरण करने वाले सरकार के निर्णय का समर्थन करने का निर्णय लिया जा चुका है। आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ. के निर्णय का लाभ उठाते हुये रक्षा उत्पादन विभाग / रक्षा मंत्रालय के द्वारा लगभग प्रत्येक दिन विभिन्न निर्देश जारी करते हुये, बड़ी तेजी से सरकार के निर्णय को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जमीनी हकीकत का आंकलन करने तथा आयुध निर्माणियों के सम्पूर्ण कार्य बल के स्पष्ट अभिमत को सूचित करने के लिये, सभी आयुध निर्माणियों में एक जनमत संग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार रक्षा मंत्रालय को यह दिखाने के लिये, कि सरकार के द्वारा आयुध निर्माणियों को विभाजित करके 07 निगमों में तब्दील करने का जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय एक बीमारू कल्पना पर आधारित है, विसंगति पूर्ण है तथा पूरी तरह से हमारे देश की सुरक्षा एवं रक्षा तैयारियों के विरुद्ध है, इसलिये महासंघों के द्वारा कर्मचारियों के बीच में एक जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार ए.आई.डी.ई.एफ., बी.पी.एम.एस., सी.डी.आर.ए., एन.पी.डी.ई.एफ. एवं ए.आई.बी.डी.ई.एफ. के द्वारा स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप दिनांक 13.09.2021 से 18.09.2021 वाले सप्ताह में किसी एक दिन जनमत संग्रह कराने का

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। जनमत संग्रह के मतपत्र का नमूना साथ में संलग्न है। निर्माणी के प्रवेश द्वार पर दो बलेट बॉक्स रखे जायें, जिसमें से एक निगमीकरण के समर्थन में काले रंग का हो तथा दूसरा निगमीकरण के विरोध में सफेद रंग का हो। हमें प्रत्येक कर्मचारी से समान रूप से सम्पर्क करके उन्हें, निगमीकरण के विरोध में तथा सेवानिवृत्ति के समय तक एक सरकारी कर्मचारी के रूप में ही बने रहने के लिये, जनमत संग्रह में अपनी पसंद जाहिर करने हेतु, शिक्षित करना होगा। पोलिंग समाप्त होने के पश्चात वोटों की गिनती की जाये तथा परिणाम की जानकारी तत्काल ही सम्बन्धित महासंघों को दी जाये, जिससे महासंघों के द्वारा सभी स्थानों की रिपोर्ट को संकलित करके सरकार को भेजा जा सके। सभी यूनियनों / संयुक्त संघर्ष समितियाँ, मतदान के परिणाम की लिखित में जानकारी निर्माणी के महाप्रबन्धक को भी देंगी। मत पत्र पर ए.आई.डी.ई.एफ., बी.पी.एम.एस. तथा सी.डी.आर.ए., का नाम भी छापा जाये। जिन निर्माणियों में एन.पी.डी.ई.एफ. तथा ए.आई.बी.डी.ई.एफ. की यूनियनों कार्य कर रही है, उन निर्माणियों में मत पत्र पर एन.पी.डी.ई.एफ. तथा ए.आई.बी.डी.ई.एफ. का भी नाम छापा जाये।

## RESULT OF THE REFERENDUM MAY BE FORWARDED TO THE FEDERATIONS IN THE FOLLOWING FORMAT

- 1) Name of the Factory \_\_\_\_\_
- 2) No. of employees of the Factory \_\_\_\_\_
- 3) No. of Employees participated in the Referendum \_\_\_\_\_
- 4) No. of Employees voted against Corporatisation \_\_\_\_\_
- 5) No. of Employees voted in support of Corporatisation \_\_\_\_\_

(To be signed by the General Secretaries of the Unions which conducted the Referendum with Federation name)



**(सी.श्रीकुमार)**

महामन्त्री

ए.आई.डी.ई.एफ.

09444080885 / 9421081035 (Whatsapp)

defempfed@gmail.com

भवदीय  


**(मुकेश सिंह)**

महामन्त्री

बी.पी.एम.एस.

09335621629

gensecbpms@yahoo.co.in



**(विजय पी. ध्यानी)**

महामन्त्री

सी.डी.आर.ए.

09999766016

gscdra@gmail.com



**(वी. वेलुस्वामी)**

महामन्त्री

एन.पी.डी.ई.एफ.

9444471845

velu10swamy@gmail.com



**(मुकेश कुमार)**

महामन्त्री

ए.आई.बी.डी.ई.एफ.

9540513330

**जनमत संग्रह - 2021**

निर्माणी का नाम \_\_\_\_\_

ए.आई.डी.ई.एफ., बी.पी.एम.एस., सी.डी.आर.ए. (जिन निर्माणियों में एन.पी.डी.ई.एफ. तथा ए.आई.बी.डी.ई.एफ. की सम्बद्ध यूनियनें हो वहाँ पर इनका भी नाम मत पत्र पर छापा जाये।)

**मतपत्र का नमूना**

- 1) मैं निगमीकरण का विरोध करता हूँ एवं उसे खारिज करता हूँ तथा  
सरकारी कर्मचारी / रक्षा असैनिक कर्मचारी के रूप में ही रहना चाहता हूँ।
- 2) मैं आयु निर्माणियों के निगमीकरण का  
समर्थन करता हूँ।

